भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 764
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना का विस्तार

764. **श्री दिलेश्वर कामैतः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026 की शुरुआत तक सौ असेवित या अल्पसेवित विमानपत्तनों को संचालित करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उड़ान योजना के अंतर्गत असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में विमानपत्तनों के निर्माण के अगले चरण के लिए क्या रोडमैप और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इसकी समय-सीमा क्या है और कौन-से स्थान प्रस्तावित किए गए हैं;
(ग) उड़ान योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बढ़े हुए बजटीय आवंटन का उपयोग उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अंतिम छोर तक संपर्क को बढ़ाने के लिए किस प्रकार किया जाएगा; और
(घ) क्या सरकार ने द्वीप क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीप्लेन व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) दिनांक 20.07.2026 तक, 'उड़ान' योजना के तहत देशभर में 17 हेलीपोर्टों और 02 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 95 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले कुल 679 आरसीएस मार्ग प्रचालनरत किये गए है।

(ख) और (ग) देशभर के टियर 2 एवं टियर 3 शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 'उड़ान' योजना का अगला चरण दिनांक 04.07.2026 को शुरू किया गया था, जिसमें अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लक्षित किया गया है। इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है, जिसमें पर्वतीय, उत्तर-पूर्वी और आकांक्षी (एचआईएनईआर) राज्यों/जिलों में एयरोड्रोम विकास के लिए 12,159 करोड़ रुपये और 200 हेलीपोर्टों के विकास के लिए 3,661 करोड़ रुपये शामिल हैं।

यह योजना चैलेंज मोड फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है जिसके तहत राज्य सरकारें विकास के लिए हवाईपट्टियों को निर्दिष्ट कर सकती हैं। भूमि की उपलब्धता, अवसंरचना की तैयारी, तकनीकी और परिचालन व्यवहार्यता, यातायात क्षमता, वैधानिक मंजूरियों और राज्य सरकारों के समर्थन के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 में, यह घोषणा की गई थी कि लास्ट-माइल एवं दूरस्थ कनेक्टिविटी में वृद्धि करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार सीप्लेन विनिर्माण के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करेगी और सीप्लेन परिचालनों का समर्थन करने के लिए सीप्लेन व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना शुरू करेगी। यह योजना वर्तमान में तैयार किए जाने के चरण में है।

*****